

## भारतीय कृषि का रूपांतरण

यह एडिटोरियल 24/06/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "How Shivraj Singh Chouhan can transform Indian agriculture" लेख पर आधारित है। इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित चुनौतियों की चर्चा की गई है और भारत की नवगठित सरकार के लिये संभावित समाधानों का सुझाव दिया गया है।

### प्रलिमिस के लिये:

**कृषि एवं कसिन कल्याण मंत्रालय (MoA&FW), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), लघु एवं सीमांत कसिन (SMF), कृषि जनगणना, प्रधानमंत्री कसिन सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि संचार योजना (PMKSY), ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)**

### मेन्स के लिये:

भारत में कृषि का महत्व, भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, कृषि से संबंधित प्रमुख पहल, भारत में कृषि क्षेत्र के सुधार हेतु आगे की राह।

हाल ही में शविराज सहि चौहान को नवगठित सरकार में **कृषि एवं कसिन कल्याण मंत्रालय (MoA&FW)** और **ग्रामीण विकास मंत्रालय** का प्रभार सौंपा गया है।

उनकी नियुक्तिउनके सदिध ट्रैक रफिकॉर्ड और कृषि एवं ग्रामीण विकास की गहरी समझ के कारण रणनीतिक महत्व रखती है। उन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उनके नेतृत्व में राज्य ने वर्ष 2005-06 से 2023-24 तक प्रतविष्ट 7% की जीडीपी वृद्धि और 6.8% प्रतविष्ट की कृषि-जीडीपी वृद्धिदर्ज की, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक रही।

MoA&FW को भारतीय कृषि क्षेत्र के समक्ष विद्यमान उन दबावपूरण मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिये तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है जो ग्रामीण विकास एवं समग्र आर्थिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसकी सबसे प्रमुख प्राथमिकता 5% से अधिकी की वार्षिक कृषि-जीडीपी वृद्धि हासिल करना और कसिनों की आय में तेज़ी से वृद्धि करना होना चाहिये।

### भारत में कृषि का महत्व:

#### जीडीपी में योगदान:

- पछिले कुछ दशकों में भारत की **जीडीपी** में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है लेकिन यह क्षेत्र अभी भी एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है।
- अरथव्यवस्था के **कुल सकल मूल्यवरदधति (GVA)** में कृषि की हस्सेदारी वर्ष 1990-91 के 35% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15% तक गई है। यह गरिवट कृषि GVA में गरिवट के कारण नहीं बल्कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र GVA में तेज़ी से वसितार के कारण आई है।

#### रोज़गार:

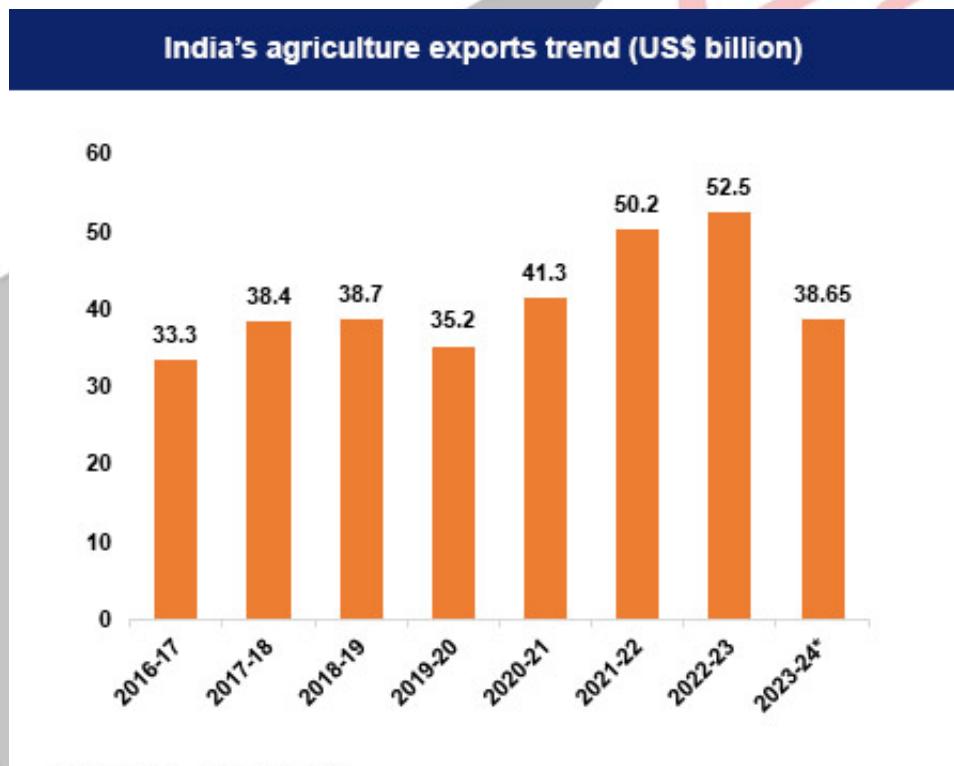
- कृषि क्षेत्र, देश में सबसे बड़ा नियोक्ता होने की स्थिति रखता है।
- सांख्यकी और कार्यकरम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** द्वारा आयोजित **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कार्यबल का लगभग 45.76% कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संलग्न था।

#### खाद्य सुरक्षा:

- भारत मुख्य खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से चावल और गेहूँ के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश अपनी बढ़ती आबादी को खाद्य प्रदान कर सकता है।
  - भारत दूध, दाल और मसालों का विशेष का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि गेहूँ विशेष की सबसे बड़ी मवेशी आबादी (भैंस) पाई जाती है। इसके साथ ही भारत में गेहूँ, चावल और कपास की खेती के लिये कुल भूमिका सबसे बड़ा क्षेत्र मौजूद है।
  - भारत चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, मछली, भेड़ एवं बकरी का मांस, फल, सब्जियाँ और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक

۴

- **सारवजनिक वत्तिरण परणाली (PDS)** और खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम जैसी सरकारी पहलें सभी नागरिकों को कफियती भोजन उपलब्ध कराने के लिये कृषिउत्पादन पर निभर करती है।
    - PDS के तहत वर्तमान में गेहूँ, चावल, चीनी और केरोसिन जैसी वस्तुओं को लाभारथयों के बीच वत्तिरण हेतु राज्यों/संघ शास्ति प्रदेशों को आवंटित किया जा रहा है।
    - कुछ राज्य/संघ शास्ति प्रदेश PDS आउटलेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर उपभोग की अन्य वस्तुएँ (जैसे दाल, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि) भी वत्तिरति करते हैं।
  - **भूमिउपयोग:**
    - भारत में कृषिभूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50% से कुछ अधिक है। यह वशिव के कसी भी देश में कुल भूमि के प्रतशित के रूप में सर्वाधिक है।
    - देश में लगभग 195 मलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जिसमें से लगभग 63 प्रतशित वर्षा पर निभर है (लगभग 125 मलियन हेक्टेयर) जबकि 37 प्रतशित सचिति (70 मलियन हेक्टेयर) है।
  - **वदिशी मुद्रा:**
    - कृषि नियात भारत की वदिशी मुद्रा आय अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चावल, मसाले, कपास, फल और सब्जियों जैसी वस्तुओं का वैश्वाकि स्तर पर नियात किया जाता है, जिससे राजस्व प्राप्त होता है और व्यापार घाटे को संतुलित किया जाता है।
    - अप्रैल-जनवरी 2024 में कृषिउत्पादों के नियात का कुल मूल्य 38.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वर्ष 2022-23 में भारत से कृषि नियात 52.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का रहा।
  - **सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संवहनीयता:**
    - कृषिभारत की सांस्कृतिक वरिसत और सामाजिक ताने-बाने से गहराई से संबंधिति है। यह ग्रामीण परंपराओं, त्योहारों और सामुदायिक जीवन को आकार देती है तथा यह सांस्कृतिक पहचान और ग्रामीण सामंजस्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
    - मृदा की उर्वरता, जल और जैवविविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिये संवहनीय कृषि पद्धतयों महत्वपूर्ण हैं। पारंपरिक खेती के तरीके और आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और दीर्घकालिक संवहनीयता को बढ़ावा देने का लक्षण रखती हैं।



Note: \*Until January 2024

Source: The Ministry of Commerce & Industry

भारत में कृषकिक्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

## ■ છોટી ભૂમિજોત:

- ० भारत में कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग छोटी जोतों में विभाजित है, जो कसिानों की सम्मानजनक आजीविका कमाने की क्षमता को सीमित करता है।
  - ० कृषि जनगणना से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, परचिलन जोतों का औसत आकार वर्ष 1970-71 के 2.28 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 1980-81 में 1.84 हेक्टेयर, वर्ष 1995-96 में 1.41 हेक्टेयर और वर्ष 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर रह गया है।
  - ० भारत की कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, 86.1 प्रतशित भारतीय कसिन छोटे और सीमांत कसिन (SMF) हैं, जनिके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है।

#### ■ आर्थिक कठनाइयाँ:

- भारत में एक कसिन की औसत मासिक आय अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जो कृषि क्षेत्र में उन लोगों के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियों को उजागर करती है।
  - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की वर्ष 2019 की एक रपोर्ट के अनुसार, मज़दूरी, फसल उत्पादन और पशुधन सहित सभी सरों से प्राप्त एक कसिन परवार की औसत मासिक आय लगभग 10,218 रुपए थी।
- छोटे और सीमांत कसिनों को प्रायः ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कफियती ऋण की सीमति उपलब्धता आधुनिक कृषि उपकरण, गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरकों में निवाश करने की उनकी क्षमता को सीमति करती है, जिससे उनकी उत्पादकता में बाधा आती है।
  - वर्ष 2019 में आयोजित NSS सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में आधे से अधिक कृषक परवार ऋणग्रस्त हैं।

#### ■ मृदा कृषण और जल की कमी:

- कृषि के लिये जल का अत्यधिक दोहन जलभूतों में जल स्तर को कम कर रहा है, जिससे प्रमुख खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में स्थिरता करना असंभव होता जा रहा है।
  - भारत के लगभग 90 प्रतिशत भू-जल का उपयोग कृषि के लिये किया जाता है
- अनुचित भूमि उपयोग प्रथाएँ, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और अपर्याप्त मृदा संरक्षण उपाय मृदा कृषण एवं कटाव में योगदान करते हैं।
  - इनके कारण मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, कीटों एवं बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और अंततः कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है।

#### ■ अपर्याप्त कृषि अवसंरचना:

- अपर्याप्त भंडारण एवं कोल्ड चेन सुधारिएँ, अपर्याप्त ग्रामीण सड़कें और बाजारों तक सीमति पहुँच, उत्पादन के बाद होने वाली हानि (post-harvest losses) में योगदान करती हैं।
- इन अवसंरचना अंतरालों के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और कसिनों की अपनी उपज के लिये उचित मूल्य प्राप्त करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

#### ■ कृषि अनुसंधान में नमिन नविश:

- कृषि अनुसंधान और विद्यार्थी सेवाओं में नविश मुद्रासंकट के साथ तालमेल नहीं रख पाया है, जिससे वास्तविक वित्तीयोषण में कमी आई है।
- इस नमिन नविश के कारण नवोन्मेषी और कुशल कृषि प्रदर्शनियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।

#### ■ पुरानी पड़ चुकी कृषि प्रदर्शनियाँ:

- भारतीय कसिनों का एक बड़ा हसिसा अभी भी पारंपरिक और पुरानी पड़ चुकी कृषि प्रदर्शनियों पर निर्भर है।
- सूचना तक सीमति पहुँच, आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी और बदलाव के प्रति प्रतिरोध, उन्नत कृषि प्रदर्शनियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- कृषि अनुसंधान में नमिन नविश के कारण नवोन्मेषी और कुशल कृषि प्रदर्शनियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।

#### ■ बाजार की अस्थिरता और मूल्य में उत्तार-चढ़ाव:

- भारत में कसिनों को प्रभावी बाजार संपर्कों, बिलिंगों और मूल्य सूचना की कमी के कारण मूल्य में उत्तार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इससे वे मूल्य शोषण और अपने नविश पर अनश्वित रिट्रैट के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- भारतीय नीति निर्माता प्रायः प्रतिक्रिया WTO नियमों के प्रभावों को समझने और उसे कम करने के लिये संघर्ष करते हैं।
- उपभोक्ताओं के लिये खाद्य कीमतों को कम रखने की वैश्विक प्राथमिकताओं के प्रतिक्रिया रूप कृत्रिम रूप से फारम-गेट मूल्यों में कमी आती है, जिससे खेती आर्थिक रूप से अव्यवहारिक और प्रयावरणीय रूप से असंवहनीय हो जाती है।

#### ■ विषम नीतिगत चुनौतियाँ:

- नीतिगत चुनौतियाँ इसलिये सामने आती हैं क्योंकि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बहुत कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराती है। इससे कसिनों को उनकी फसलों के लिये मलिन वाली कीमतें कम हो जाती हैं, जिससे उनके लिये प्राप्ति आय अर्जित करना कठिन हो जाता है।
- इसके अतिरिक्त, विषम उर्वरक सब्सिडी इसके अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे मानव स्वास्थ्य और प्रयावरणीय संवहनीयता दोनों पर प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ता है।

#### ■ जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ:

- बढ़ते हुए अनियमित मौसम पैटर्न ने कृषि उत्पादकता को प्रभावित किया है।
- अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और बाढ़, चक्रवात एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएँ भारत के कृषि उद्योग के लिये गंभीर चुनौतियाँ पेश करती हैं। इन घटनाओं के प्रतिक्रिया रूप फसल की हानि, पशुधन की मौत और कसिनों के लिये भेद्यता बढ़ सकती है।
- जलवायु परिवर्तन प्रभाव आकलन के अनुसार, अनुकूलन उपायों को अपनाए बना, भारत में वर्षा आधारित चावल की पैदावार वर्ष 2050 तक 20% और वर्ष 2080 तक 47% कम हो जाने का अनुमान है।

## कृषि से संबंधित प्रमुख पहलें:

- [प्रधानमंत्री कसिन सम्मान निधि \(PM-KISAN\)](#)
- [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना \(PMFBY\)](#)
- [मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना](#)
- [प्रधानमंत्री कृषि स्थिरता योजना \(PMKSY\)](#)
- [ई-राष्ट्रीय कृषि बिजार \(e-NAM\)](#)
- [राष्ट्रीय सतत कृषि भिजिन](#)
- [परंपरागत कृषि विकास योजना \(PKVY\)](#)

- डिजिटल कृषि मिशन
- एकीकृत कसिन सेवा मंच (UFAP)
- कृषि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NEGP-A)
- प्रश्नोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

## भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहये?

- समग्र कृषि दृष्टिकोण:
  - कृषि को उत्पादन, विपणन और उपभोग को शामल करते हुए एक व्यापक खाद्य परणाली के रूप में देखा जाए।
  - संस्थागत सुधारों के माध्यम से ऋण, इनपुट और कसिन-केंद्रति सलाह तक पहुँच में सुधार लाया जाए।
  - जैविक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए।
  - सामूहिक सौदेबाजी के लिये **कृषक-उत्पादक संगठनों (FPOs)** और सहकारी समतियों को सुदृढ़ बनाया जाए।
- मूल्य शृंखला विकास:
  - उच्च मूल्य वाली फसलों, डेयरी उत्पादों, मतस्य पालन और मुर्गीपालन के लिये मज़बूत मूल्य शृंखला का नरिमाण किया जाए। इसे प्राप्त करने के लिये नज़ीर क्षेत्र, सहकारी समतियों और कसिन-उत्पादक कंपनियों के साथ सहयोग स्थापित किया जाए।
  - मूल्य शृंखला विकास को बढ़ाने के लिये उदयोग में **उत्पादन आधारति प्रोत्साहन (PLI) योजना** के समान सार्वजनिक-नज़ीर भागीदारी (PPP) और योजनाओं को लागू किया जाए।
- प्रौद्योगिकियाँ और बाजारों तक पहुँच:
  - उत्पादकता और आय में सुधार के लिये कसिनों के लिये सरकारी प्रौद्योगिकियों और वैश्वकि बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।
  - नरियात प्रतिविधी, व्यापारियों पर स्टॉक सीमा एवं बाजार मूल्य दमन की रणनीति को कम कर कसिनों की तुलना में उपभोक्ताओं के पक्ष में नीतिगत पूरवाग्रहों को संबोधित किया जाए।
  - कृषि अनुसंधान एवं विकास (R&D) और वित्तीय सेवाओं पर व्यय को कृषि-जीडीपी के कम से कम 1% तक बढ़ाया जाए, जिसका वर्तमान स्तर 0.5% से कम है।
- उर्वरक सबसिडी में सुधार:
  - **उर्वरक सबसिडी** को कृषि एवं कसिन कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाए। वर्तमान में सबसिडी का प्रबंधन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसका कसिनों के साथ प्रत्यक्ष संपरक सीमित है।
  - नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के उपयोग में असंतुलन को दूर करने के लिये उर्वरक सबसिडी वितरण को तरक्सित बनाया जाए।
  - उर्वरक सबसिडी के लिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में प्रविरत्न कसिनों को रासायनिक और जैव-उर्वरकों या प्राकृतिक खेती के तरीकों के बीच चयन कर सकने की अनुमति देगा।
- समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा:
  - व्यापक **फसल बीमा योजनाओं** और आय सहायता कार्यक्रमों को लागू किया जाए।
  - कृषि आय को स्थिर करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद सुनिश्चित किया जाए।
- जलवायु-प्रत्यास्थी कृषि:
  - **जलवायु-प्रत्यास्थी या जलवायु-कृषि** के लिये नविश संसाधनों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि गिरीषम एवं बाढ़ प्रतिरिधी बीजों में अधिक नविश किया जाए।
    - जल संसाधनों में अधिक नविश न केवल उनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिये बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिये भी आवश्यक है कि जिल का अधिक विकास पूरण तरीके से उपयोग किया जा रहा है।
    - 'प्रतिबूँद अधिक फसल' केवल एक नारा नहीं रहे, बल्कि वास्तविक रूप से साकार हो। परशुरद्ध कृषि के एक भाग के रूप में ड्रपि, सपरकिलर और संरक्षित खेती को आज की तुलना में बहुत बढ़े पैमाने पर अपनाने की आवश्यकता है।

## निष्कर्ष:

कृषि विकास के लिये अनुकूल माहौल का नरिमाण करने वाले नीतिगत सुधारों को अपनाने से भारत अपने कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता को साकार कर सकने में सक्षम होगा, जिससे यह राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बन जाएगा। यह प्रविरत्न लाखों कसिनों के लिये स्थायी आजीविका को सुरक्षित करेगा, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाएगा, समावेशी विकास को बढ़ावा देगा और भारत को कृषि निवाचार एवं संवहनीयता में वैश्वकि स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करेगा।

**अभ्यास प्रश्न:** धारणीय आजीविका सुनिश्चित करने, खाद्य सुरक्षा को उन्नत करने तथा देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के क्रम में भारत के कृषि क्षेत्र में तत्काल नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। टपिकों कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न:**

प्रश्न. नमिनलखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2014)

कार्यक्रम/परियोजना

मंत्रालय

1. सूखा - प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	कृषि और कसिन कल्याण मंत्रालय
2. मरुस्थल विकास कार्यक्रम	प्रयोग्यवन, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय
3. वर्षा पूर्ति क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय

उपर्युक्त युगमें में से कौन-सा/से सही सुमेलति है? हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (d)

**प्रश्न.** भारत में नमिनलखिति में से कसि कृषि में सार्वजनिक नविश माना जा सकता है? (2020)

1. सभी फसलों की कृषिउपज के लिये नयनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
2. प्राथमिक कृषिउपज समतियों का कम्पयूटरीकरण
3. सामाजिक पूँजी का विकास
4. कसिनों को निःशुलक विद्युत आपूर्ति
5. बैंकिंग परणाली द्वारा कृषिउपजों की माफी
6. सरकारों द्वारा शीत भण्डारण सुवधाओं की स्थापना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनायिः

- (a) केवल 1, 2 और 5
- (b) केवल 1, 3, और 4 और 5
- (c) केवल 2, 3 और 6
- (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: C

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/transforming-indian-agriculture>